

Bharatiya Janata Party

(Central Office)

11, Ashok Road, New Delhi – 110001

Tel. No. : 23005700; Fax : 23005787

Date : January 20, 2013

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं पंजाब मामलों के सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु का प्रेस वक्तव्य

नई दिल्ली 20 जनवरी:

भ्रष्टाचार और महंगाई के द्वारा आम आदमी के साथ बीते नौ साल तक किए गए विश्वासघात के कारण यूपीए सरकार की अगुवाई करने वाली कांग्रेस को जयपुर में चल रहे अपने चिंतन शिविर का नाम बदल कर प्रायश्चित शिविर कर लेना चाहिए। इस सरकार के बीते नौ साल के कार्यकाल में न केवल महंगाई और भ्रष्टाचार के तमाम कीर्तिमान ध्वस्त हो गए हैं, बल्कि इस दौरान सरकार देश के लिए शहादत देने वाले बहादुर जवानों के सम्मान की भी रक्षा नहीं कर सकी।

आम आदमी के हितों के नाम पर सत्ता में आई कांग्रेस ने सर्वाधिक नुकसान आम आदमी का ही किया है। साल 2009 की अपनी दूसरी पारी में कांग्रेस ने सौ दिनों के अंदर महंगाई और भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा किया था। लेकिन महंगाई और भ्रष्टाचार न केवल चरम पर हैं, बल्कि इस मोर्चे पर सरकार ने सारे पुराने कीर्तिमान भी ध्वस्त कर दिए हैं। चिंतन शिविर से एक दिन पहले डीजल और बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों की कीमतों में बढ़ोत्तरी के बाद फिर से कांग्रेस आम आदमी का राग अलाप रही है। इसलिए कांग्रेस को चिंतन करने के बदले कमरतोड़ महंगाई और टूजी, सीडब्लूजी, कोल ब्लॉक आवंटन, आदर्श सोसाइटी, कॉमनवेल्थ खेल जैसे दर्जनों रिकार्डतोड़ भ्रष्टाचार के लिए प्रायश्चित करना चाहिए।

आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी कांग्रेसनीत यूपीए सरकार पूरी तरह से विफल रही है। सरकार की अकर्मण्यता के कारण नक्सली न केवल वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसा रहे हैं, बल्कि अद्वैतसैनिक बलों की बर्बर हत्या करने के बाद उनके पेट को चीर कर बम भी लगा रहे हैं। दिल्ली जहां की कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के हाथ में है वहां बीते दिनों हुए शर्मनाक और रॉंगेट खड़े कर देने वाले सामूहिक बलात्कार की घटना ने आंतरिक सुरक्षा की पोल खोल कर रख दी है। हालात इतने शर्मनाक हैं कि इस घटना के बाद भी देश की राजधानी में बलात्कार के 54 मामले दर्ज हुए हैं जो कि चाकचौबंद सुरक्षा व्यवस्था का दावा करने वाली सरकार के मुंह पर तमाचा है।

कांग्रेसनीत यूपीए सरकार ने देश का नाम दुनिया भर में बदनाम किया है। मुंबई हमला मामले में शामिल आतंकवादी खुलेआम घूम रहे हैं लेकिन दूसरी ओर सरकार पाकिस्तान के साथ विदेशी दबाव में शांति वार्ता प्रक्रिया को शर्मनाक ढंग से जारी रखे हुए है। सरकार की इन्हीं दुलमुल नीतियों के कारण नियंत्रण रेखा पर दो सैनिकों की बर्बर हत्या हुई, लेकिन सरकार करारा जवाब देने के बदले बगलें झांकती नजर आई। इसी प्रकार विदेशी दबाव में खुदरा व्यापार क्षेत्र में एफडीआई मुद्दे पर कांग्रेस ने करोड़ों लोगों के रोजगार की कीमत पर अपनी सरकार तक को दांव पर लगा दिया। इसी प्रकार काला धन वापसी के मामले में विदेशी बैंकों द्वारा जानकारी देने पर राजी होने के बावजूद सरकार ने इन बैंकों में खाताधारकों की जानकारी लेने में जानबूझ कर उदासीनता दिखाई। सरकार को कुछ खाताधारकों के नाम भी मिले, लेकिन सरकार इन्हें सार्वजनिक करने के बदले छिपा गई।

यूपीए सरकार के बीते नौ साल के कार्यकाल में लोकतंत्र के साथ साथ लोकतांत्रिक व संवैधानिक संस्थाओं को भी कमजोर करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी। बाबा रामदेव और अण्णा हजारे के आंदोलन को बल और छल से दबाने की कोशिश हुई तो आजाद भारत में पहली बार देश के प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सीएजी जैसी संस्था के खिलाफ सार्वजनिक रूप से विषवमन किया। मंत्रिमंडल के सदस्य चुनाव आयोग पर भी हमला करने से नहीं चूके। इन दोनों ही संस्थाओं की ईमानदारी पर आजाद भारत में पहली बार सरकार और उसमें शामिल मंत्रियों ने अंगुली उठाई।

इस सरकार ने देश की धर्मनिरपेक्ष छवि को भी तार तार करने की कोशिश की। वोट बैंक की राजनीति के चलते मजहब आधारित आरक्षण के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की तो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे मतांध और राष्ट्रविरोधी नेताओं को महज उसकी पार्टी का समर्थन पाने के लिए प्रश्रय दिया। चिंतन शिविर में सार्थक चिंतन के बदले कांग्रेस लोगों को भरमाने की नई रणनीति तैयार करने में जुटी है। देश की जनता हकीकत जानती है और अब वह कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली। हां, अगर कांग्रेस अपने चिंतन शिविर का नाम बदल कर प्रायश्चित शिविर रखती और अपने कुकर्मों का सही अर्थों में प्रायश्चित करती तो देश इस शिविर की ओर ध्यान देता।

(O.P. KOHLI)
Headquarter Incharge